

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
एफ0टी0सी0 बिल्डिंग, प्रथम तल,
सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड,
देहरादून

न्याय अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 16 अप्रैल, 2008

विषय-मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सृजित पदों की निरन्तरता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 36/xxxvi(1)एक/07-184/01टी0सी0-1 दिनांक 22 फरवरी, 2007 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु मूल रूप में शासनादेश संख्या- 106-एक/न्याय विभाग/2002, दिनांक 1-5-2002 द्वारा सृजित 23 पदों, मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति हेतु, शासनादेश संख्या- 12-एक(5)/न्याय विभाग/2003, दिनांक 21-8-2003, द्वारा सृजित 02 पदों, जनपद बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं चम्पावत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या - 15-एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 25-7-2003 द्वारा सृजित कुल 06, पदों जनपद उधमसिंह नगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या-16-एक(5)/न्याय विभाग/2003 दिनांक 20-8-2003 द्वारा सृजित 02 पदों, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु शासनादेश संख्या-5-एक(5)/ छत्तीस (1)/न्यायअनु0/2005 दिनांक 11-2-2005 द्वारा सृजित 01 पद एवं शासनादेश संख्या 8-एक(5)/न्याय/न्याय विभाग/2003 दिनांक 28-6-2005 द्वारा सृजित 02 पदों अर्थात् कुल 36 पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 1-3-2008 से 28-2-2009 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्राधिकरणों एवं समिति के कार्यालय में पद धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होगी ।

92

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00- आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-05-राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण-00" के अन्तर्गत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिये लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-06-जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय झाप संख्या- ए-1-1270/76-दस, दिनांक 20 जुलाई, 1968 सपठित कार्यालय झाप संख्या- ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 7-11-92, (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव,

संख्या-126 (1)/xxxvi(1)एक/08-184टी०सी०/2008समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
- 2- महानिबन्धक, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
- 3- जिला न्यायाधीश बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चम्पावत एवं उधमसिंहनगर ।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर /नैनीताल/ बागेश्वर/ रुद्रप्रयाग/ चम्पावत ।
- 5- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(आलीक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,